

“अगर चीन के साथ संबंध तोड़ना अमेरिका के लिए कठिन है, तो रूस के साथ संबंध जोड़ना और अधिक मुश्किल हो सकता है।”

भारत चुनावी माहौल से घिरा हुआ है, जिसके कारण भारत को दुनिया के दो सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक रिश्तों में हो रही उथल-पुथल को समझने के लिए बहुत कम समय मिल रहा है। जिसमें से पहला विश्व की प्रमुख आर्थिक शक्तियां अर्थात् संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच विवाद है, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 40 प्रतिशत योगदान देते हैं। दूसरा, विश्व की शीर्ष सैन्य शक्तियों अर्थात् अमेरिका और रूस के बीच है।

यदि पिछले सप्ताह चीन के साथ व्यापार पर अमेरिकी वार्ता का पतन देखने को मिला है, तो इस सप्ताह वाशिंगटन का ध्यान रूस के साथ उत्पादक जुड़ाव को फिर से शुरू करने पर केन्द्रित होते देखा जा सकता है। निश्चित तौर पर यह कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली में अगली सरकार का पहला कार्य अमेरिका, चीन और रूस के संबंधों में अस्थिरता का सामना करना होगा। जून में शिखर बैठक की एक जोड़ी - बिश्केक, किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन और जापान के ओसाका में जी-20, भारतीय नेतृत्व के आंकलन के लिए एक नया अवसर प्रदान करती है।

अमेरिका और चीन के बीच गहरी आर्थिक निर्भरता, वाशिंगटन और बीजिंग के बीच व्याप्त संघर्ष पर थोड़ा विराम लगाती है।

जैसा कि अमेरिका-चीन व्यापार वार्ता के कगार पर हैं, ट्रम्प ने 200 बिलियन डॉलर चीनी निर्यात पर टैरिफ बढ़ा दिया है। अगर अगले कुछ हफ्तों में कोई सौदा नहीं हुआ, तो ट्रम्प ने चीन से सभी आयातों पर नए टैरिफ लगाने की भी धमकी दी है जो 2018 में 540 बिलियन डॉलर का था। व्यापार पर ट्रम्प के आत्मविश्वास में वृद्धि दो कारकों से प्रेरित प्रतीत होती है। एक धारणा यह भी है कि अमेरिका चीन की तुलना में व्यापार युद्ध से होने वाले नुकसान से बेहतर तरीके से निपट सकता है। दूसरा, अन्य दोनों राष्ट्रों के बीच अन्योन्याश्रय की असंयमित प्रकृति है। चीन निर्यात की तुलना में बहुत कम (2018 में 121 बिलियन डॉलर) आयात करता है। यह महत्वपूर्ण रूप से चीन को एक छोटा लक्ष्य प्रस्तुत करता है, जिस पर प्रतिशोधी टैरिफ लगाया जाता है।

अमेरिका के लिए समस्या अब केवल चीन के साथ बड़े पैमाने पर व्यापार घाटे के बारे में नहीं है। वाशिंगटन में एक बढ़ती भावना यह है कि बीजिंग से खतरा 'प्रणालीगत' है और अमेरिका को इसका उचित जवाब देना चाहिए। वाशिंगटन चीन पर अमेरिका से बौद्धिक संपदा की चोरी का आरोप लगा रहा है। यह 5G टेलीकॉम नेटवर्क को विकसित करने की अनुमति देने के सामने हितैषियों और सहयोगियों की पैरवी कर रहा है। वाशिंगटन दक्षिण चीन सागर में चीन की मुखर नीतियों के खिलाफ और ताइवान को सामरिक समर्थन के एक उपाय को नवीनीकृत करने पर जोर दे रहा है।

दो हफ्ते पहले एक प्रमुख भाषण में, अमेरिकी विदेश विभाग में नीति नियोजन के प्रमुख कीरोन स्कनर ने जोर देकर कहा था कि चीन से खतरा सभ्यतागत था। 'चीन में हमारे पास एक आर्थिक प्रतियोगी है, हमारे पास एक वैचारिक प्रतियोगी है, जो वास्तव में एक तरह की वैश्विक पहुंच चाहता है, जिसकी हममें से कईयों ने कुछ दशक पहले तक उम्मीद नहीं की थी और मुझे लगता है कि यह वास्तव में काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पहली बार है जब हमारा सामना महान शक्ति से हो रहा है।'

चीन को एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी के रूप में पेश करते हुए स्कनर ने रूस के बारे में भी कुछ कहा जिस पर दिल्ली को विशेष ध्यान देना चाहिए।

स्कनर के अनुसार सोवियत संघ के साथ शीत युद्ध मुकाबला "पश्चिमी परिवार के भीतर एक लड़ाई थी। कार्ल मार्क्स एक जर्मन यहूदी थे, जिन्होंने एक दर्शनशास्त्र विकसित किया जो राजनीतिक विचार के बड़े शरीर के भीतर था।" जबकि सोवियत संघ

के साथ कम से कम सीमित सहयोग की गुंजाइश थी। स्किकनर ने कहा, 'यह चीन के साथ वास्तव में संभव नहीं है। यह वास्तव में एक अलग सभ्यता और एक अलग विचारधारा के साथ लड़ाई है।'

ट्रम्प प्रशासन के भीतर रूस को पश्चिम का बड़ा हिस्सा लगातार माना जाता रहा है और इसलिए इसे बीजिंग से अलग माना जाना चाहिए। रूस के साथ सकारात्मक संबंधों का सबसे बड़ा हिमायती कोई और नहीं बल्कि ट्रम्प है। लेकिन वाशिंगटन में राष्ट्रपति के विचारों का समर्थन करने वाले बहुत ही कम दिख रहे हैं और 2016 के राष्ट्रपति चुनावों के दौरान ट्रम्प के पक्ष में रूसी हस्तक्षेप के आरोपों ने ट्रम्प को एक अजीब स्थिति में डाल दिया था।

आधिकारिक जाँच में ट्रम्प अभियानकी रूस के साथ किसी भी तरह की मिलीभगत नहीं पायी गयी, जिससे ट्रम्प को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तक अपनी पहुँच को नवीनीकृत करने का फिर से मौका मिल गया। कुछ दिनों पहले पुतिन के बुलावे के बाद, ट्रम्प ने इस सप्ताह के पहले परामर्श के लिए अपने राज्य सचिव माइक पोम्पियो को रूस भेजा है। इस वार्ता में वेनेजुएला से लेकर सीरिया तक और उत्तर कोरिया पर हथियार नियंत्रण जैसे कई मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है।

अगर चीन के साथ संबंध तोड़ना अमेरिका के लिए कठिन है, तो रूस के साथ संबंध जोड़ना और अधिक मुश्किल हो सकता है। कोई भी रूसी सौदा - छोटा या बड़ा - वाशिंगटन में राजनीतिक प्रतिरोध का कारण बनेगा। जबकि मास्को में कुछ लोगों का यह मानना है कि ट्रम्प के पास रूस के साथ आगे बढ़ने के लिए राजनीतिक विस्तार है।

जिस भी तरफ महान शक्ति गतिशील होगी, इसके कई परिणाम होंगे, जिनमें से कुछ बुरे होंगे और कुछ अच्छे परिणाम होंगे। चाहे ट्रम्प किसी सौदे में कटौती करे या चीन के साथ आर्थिक युद्ध को आगे बढ़ाये, दिल्ली अपनी सुस्त व्यापार नीति के साथ आगे बढ़ना जारी नहीं रख सकता है। दूसरी ओर, अमेरिका, चीन और रूस के बीच के राजनीतिक संबंधों की फिर से शुरुआत दिल्ली को अस्थायी रणनीतिक अवसरों के साथ पेश कर सकती है, जिनसे जल्द से जल्दी निपटने की आवश्यकता है।

## GS World टीम...

### अमेरिका-चीन ट्रेड वार

#### चर्चा में क्यों?

- विश्व की दो बड़ी आर्थिक शक्तियों अमेरिका और चीन के बीच व्यापार को लेकर विवाद बढ़ गया।
- अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने चीन से आयात होने वाले सामानों पर शुल्क दर 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया।
- 200 अरब डॉलर (करीब 140 खरब रुपये) मूल्य की चीनी वस्तुओं पर शुल्क वृद्धि के ऐलान के बाद से अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव की स्थिति कायम है।
- जिसके बाद चीन ने अमेरिकी कार्वाय पर जवाबी कदम उठाते हुए 60 अरब डॉलर के अमेरिकी सामानों पर आयात-शुल्क बढ़ा दिया है।
- कई विशेषज्ञों का मानना है कि इससे चीन को मंदी का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका की खपत भी प्रभावित हो सकती है।
- ट्रंप प्रशासन का दावा है कि चीन की सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), रोबोटिक्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों के मामले में चीनी कंपनियों को बढ़त दिलाने की अनैतिक प्रयास करती है।

#### क्या है?

- जब दो या अधिक देश व्यापारिक कर को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं या अन्य प्रकार के व्यापारिक प्रतिबन्ध लगा देते हैं, तो इसे व्यापार युद्ध (ट्रेड वॉर) कहते हैं।
- इससे आयात होने वाली चीजों की कीमत बढ़ जाती है, जिससे वे घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पातीं। इससे उनकी बिक्री

घट जाती है।

#### व्यापार युद्ध की पृष्ठभूमि

- विश्व के लिए व्यापार युद्ध कभी भी अच्छी नहीं रहा है। पिछली बार दुनिया ने व्यापार युद्ध को 1930 के दशक में देखा था, जब देशों ने अपने व्यापार अधिशेष को बढ़ावा देने की कोशिश की थी। नतीजतन, दुनिया भर में भारी मंदी, जिसके परिणामस्वरूप 1930 के दशक में ग्रेट डिप्रेशन हुआ।
- हालांकि, पिछले 80 वर्षों में, एक पूर्ण व्यापार युद्ध का कभी प्रयास नहीं किया गया है। भारत के लिए, कम से कम अपनी आजादी के बाद, व्यापार युद्ध की कोई घटना नहीं हुई है।

#### ट्रेड वॉर का क्यों होगा भारत पर प्रभाव?

- संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट में कहा कि भारत दुनिया की शीर्ष दो अर्थव्यवस्थाओं के बीच ट्रेड वॉर से लाभ के लिए खड़े होने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
- यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट (यूएनसीटीएडी) द्वारा फरवरी में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार चीनी निर्यात में 300 बिलियन डॉलर में, जो अमेरिकी टैक्स के अधीन हैं, केवल 6% ही अमेरिका में फर्मों द्वारा चुनाव किया जाता है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि यूरोपीय संघ के सदस्यों को सबसे अधिक लाभ होने की उम्मीद है क्योंकि यूनियन के निर्यात में 70 बिलियन डॉलर बढ़ने की संभावना है।
- जापान और कनाडा प्रत्येक के निर्यात में 20 अरब डॉलर से अधिक की वृद्धि हो सकती है।
- संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार, अन्य देशों को भी ट्रेड टेंशन का लाभ हो सकता है, जिसमें वियतनाम को 5% निर्यात लाभ,

ऑस्ट्रेलिया (4.6%), ब्राजील (3.8%), भारत (3.5%), और फिलीपींस (3.2%) शामिल हैं।

### शुल्क (टैरिफ) क्या होते हैं?

- आयात पर लगने वाले कर या टैक्स, शुल्क या टैरिफ कहलाते हैं। शुल्क उस रकम का कुछ प्रतिशत होता है, जो खरीददार कीमत के रूप में विदेशी विक्रेता को चुकाते हैं।
- अमेरिका में टैरिफ को कभी-कभार ड्यूटी या लेवी भी कहा जाता है। इन्हें देशभर के 328 बंदरगाहों पर वसूलने की जिम्मेदारी कस्टम्स एण्ड बॉर्डर प्रोटेक्शन एजेंट्स पर होती है। टैरिफ, ड्यूटी या लेवी के रूप में जमा रकम अमेरिकी सरकार के खजाने में जमा होती है।
- यूएस इंटरनेशनल ट्रेड कमीशन शुल्क दरों का प्रकाशन हार्मोनाइज्ड टैरिफ शेड्यूल में प्रकाशित करता है, जिसमें हर वस्तु पर शुल्क की दर निर्धारित होती है।

### शुल्क लगाकर हासिल क्या होता है?

- शुल्क लगाकर दो चीजें हासिल होती हैं। पहली- सरकार का राजस्व बढ़ता है और दूसरी- घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण मिलता है।

- 1913 में फेडरल इनकम टैक्स लागू होने से पहले टैरिफ अमेरिकी सरकार के लिए धन जुटाने का बड़ा जरिया था।
- 1790 से 1860 तक फेडरल रेवेन्यू का 90% हिस्सा टैरिफ से ही आया करता था। इसके उलट, हाल के दिनों में फेडरल रेवेन्यू में टैरिफ का योगदान महज 1 प्रतिशत के आसपास सिमट गया।
- द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक व्यापार में वृद्धि हुई, तो टैरिफ लगाने की नीति खत्म होने लगी। विश्व व्यापार संगठन (WTO) के गठन और उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता (नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट) जैसे व्यापारिक समझौतों से टैरिफ लगाने की परंपरा पर विराम लग गया।
- अभी अमेरिका की औसत शुल्क दर 1.6 प्रतिशत है, जो दुनिया के विभिन्न देशों की न्यूनतम शुल्क दरों में एक है। यूरोपियन यूनियन की औसत शुल्क दर भी 1.6 प्रतिशत ही है।

### संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

#### 1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. ट्रेड वॉर के कारण आयात होने वाली चीजों की कीमत घट जाती है, जिससे वे घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाती हैं।
2. संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैण्ड, हांगकांग और अमेरिका जैसे देशों के साथ भारत का ट्रेड सरप्लस है।
3. जब कोई देश निर्यात की तुलना में आयात अधिक करता है तो उसे व्यापार घाटे का सामना करना पड़ता है।
4. भारत का सर्वाधिक व्यापार घाटा पड़ोसी देश चीन के साथ लगभग 63 अरब डॉलर है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सत्य हैं?

- (a) 1 और 3
- (b) 2, 3 और 4
- (c) 1, 2 और 3
- (d) 1, 2, 3 और 4

#### 1. Consider the following statements-

1. The price of imported goods gets reduced due to trade war consequently these can not compete in the domestic market.
2. India has trade surplus with countries like- USA, United Arab Emirates, Netherland, Hong Kong etc.
3. When a country imports more than its export it has to face trade deficit.
4. India has highest trade deficit with its neighbour China of approx. 63 billion dollar.

Which of the above statements are correct?

- (a) 1 and 3
- (b) 2, 3 and 4
- (c) 1, 2 and 3
- (d) 1, 2, 3 and 4

### संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न:- ट्रेड वॉर से आप क्या समझते हैं? अमेरिका और चीन के मध्य उत्पन्न ट्रेड वॉर से भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

Q. What do you mean by trade war? Discuss the impacts on Indian economy due to trade war between America and China. (250 Words)

नोट : 13 मई को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(b) होगा।